



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-03032020-216525  
CG-MH-E-03032020-216525

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2020/फाल्गुन 13, 1941

No. 90]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2020/PHALGUNA 13, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 21 फरवरी, 2020

**सं. टीएमपी/35/2016-विविध.**—भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय के 13 फरवरी, 2020 के पत्र संख्या पीडी-11033/73/2013-पीटी (भाग) के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा महापत्तन शुल्क बल्क कार्गो बर्थिंग नीति, 2016 के अंतर्गत दांडिक बर्थ किराया प्रभार की उगाही/प्रोत्साहन स्कीम के लिए एक समान प्रक्रिया, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, अधिसूचित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएमपी/35/2016-विविध

गणपूर्ति

- (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सचर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी, 2020 के 20वें दिन पारित)

पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 16 जून, 2016 के अपने पत्र संख्या पीडी-11033/73/2013-पीटी (भाग) के द्वारा महापत्तन शुल्क बल्क कार्गो बर्थिंग नीति, 2016 प्रेषित की थी। इस संबंध में, हमें 5 महापत्तन न्यासों नामतः कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी), न्यू मंगलोर पत्तन न्यास (एनएमपीटी), कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी), परादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) और वीओ चिदंबरनार पत्तन न्यास (वीओसीपीटी) से एमओएस द्वारा जारी बर्थिंग नीति से प्रवाहित निष्पादन मानकों

की उपलब्धि/अनुपलब्धि के लिए प्रोत्साहन/दांडिक स्कीम के निर्धारण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उक्त पत्तनों से प्राप्त प्रस्तावों का इस प्राधिकरण ने निपटान किया।

2.1. अब, एमओएस ने दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही के लिए एक समान प्रक्रिया के बारे में अपने 13 फरवरी, 2020 का पत्र संख्या पीडी-11033/73/2013-पीटी (भाग) भेजा है। एमओएस के उक्त पत्र कि विषय वस्तु इस प्रकार है:

- (i) एमओएस द्वारा जारी महापत्तन न्यास शुष्क बल्क कार्गो बर्थिंग नीति, 2016 विभिन्न शुष्क बल्क वस्तुओं के निष्पादन मानकों के लिए सभी महापत्तन न्यासों के लिए मानकीकृत दिशानिर्देश निर्धारित करती है। यह समग्र बर्थिंग नीति के एक भाग के रूप में निष्पादन मानक बद्ध दंड और प्रोत्साहन ढांचे की संस्तुति भी करती है। निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन/हतोत्साहन ढांचे का उद्देश्य सभी पत्तनों में उत्पादकता सुधार का निरंतर अभियान चलाना और जिन्होंने निष्पादन में अधिक उत्पादकता दर्शायी हैं उन्हें पुरस्कृत करना है।
- (ii) वीओसीपीटी ने वस्तुओं के लदान/उतरायी के लिए वीओसीपीटी द्वारा निर्धारित निष्पादन मानक प्राप्त न करने पर जलयान एजेंटों से दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही की। लेकिन, तृतीकोरण शिप एजेंट एसोसिएशन (टीएसए) ने जलयान एजेंटों पर वीओसीपीटी द्वारा दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही पर यह कहते हुए आपत्ति की कि यदि कोई दंड या प्रोत्साहन लगाया जाना है तो वह कार्गो प्रहस्तन एजेंटों जैसे शिपर/स्टीवडोर/प्राप्तकर्ता पर लगाया जाये क्योंकि वे कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों में शामिल होते हैं। टीएसए ने अपने मामले में एमओएस को अभ्यावेदन भेजा और आईपीए को भी अभ्यावेदन दिया कि एजेंटों को दांडिक बर्थ किराया प्रभारों से मुक्त किया जाए। एमओएस ने आईपीए को इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया।
- (iii) आईपीए ने सभी महापत्तनों, प्राधिकरण, फैडरेशन ऑफ शिप एजेंट एसोसिएशन (एफईडीएसए), फैडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्टीवडोर (एफएस) और फैडरेशन ऑफ फ्रेट फारवार्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएफएआई) के साथ हितधारक परामर्श किया कि दांडिक बर्थ किराया प्रभार किस पर आरोपित किये जाएं। आईपीए ने इस मामले पर विचार करने के लिए एक ग्रुप का गठन भी किया।
- (iv) ग्रुप ने, पत्तनों और अन्य हितधारकों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और उसे आईपीए को सौंपा। अपनी रिपोर्ट में, ग्रुप ने संस्तुति की है कि विभिन्न प्रकार के कार्गो के दांडिक बर्थ किराया प्रभारों को निम्नलिखित एजेंसियों से उगाहा जाये।

प्रहस्तित कार्गो का प्रकार	दांडिक बर्थ किराया प्रभार निम्नलिखित पर आरोपित हो
मशीनीकृत बल्क बर्थ	शिपिंग/पोत एजेंट
शुष्क बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो प्रहस्त करने वाली परंपरागत बर्थें	स्टीवडोर एजेंट
तरल बर्थ	शिपिंग/पोत एजेंट

ग्रुप ने यह भी सहसूस किया कि एमओपीटी, एनएमपीटी और केओपीटी के मामले में मानकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता जहां पत्तन प्रत्यक्ष रूप से कंटेनर कार्गो की संतुलित मात्रा प्रहस्त करते हैं और स्थानीयकृत व्यवस्था मौजूद है। आईपीए के शासी निकाय ने ग्रुप की संस्तुति का अनुमोदन किया है।

2.2. आईपीए द्वारा गठित ग्रुप की संस्तुतियों के आधार पर, एमओएस ने इस प्राधिकरण को, एमओपीटी, एनएमपीटी और केओपीटी को छोड़कर, सभी महापत्तनों के लिए दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही के लिए आईपीए द्वारा यथासंस्तुत समान प्रक्रिया को अधिसूचित करने का अनुरोध किया।

3.1. इस प्रकार, एमओएस के 13 फरवरी, 2020 के पत्र संख्या पीडी-11033/73/2013-पीटी (भाग) के अनुपालन में यह प्राधिकरण बर्थिंग नीति, 2016 के अंतर्गत दांडिक बर्थ किराया प्रभार उगाही के लिए/प्रोत्साहन योजना के लिए, एमओपीटी, एनएमपीटी और केओपीटी को छोड़कर सभी महापत्तनों द्वारा अनुपालन के लिए निम्नलिखित समान प्रक्रिया निर्धारित करता है:-

“बर्थिंग नीति, 2016 के अंतर्गत दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही और प्रोत्साहन देने के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा निम्नलिखित समान प्रक्रिया का अनुपालन, इस प्राधिकरण द्वारा संबंधित अनुमोदित प्रथुल्ल के अनुसार, किया जाए:

प्रहस्तित कार्गो का प्रकार	निम्नलिखित एजेंसियों को प्रोत्साहन दिया जाए और दांडिक बर्थ किराया प्रभारों की उगाही की जाए।
मशीनीकृत बल्क बर्थ	शिपिंग/पोत एजेंट
शुष्क बल्क/ब्रेक बल्क कार्गो प्रहस्त करने वाली परंपरागत बर्थें	स्टीवडोर एजेंट

तरल बर्थ	शिपिंग/पोत एजेंट
----------	------------------

3.2. इस प्रकार, महापत्तन न्यासों को, सिवा एमओपीटी, एनएमपीटी और केओपीटी के, निदेश दिया जाता है कि वे इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित अपने संबंधित प्रशुल्क आदेश/दरमान में, तदनुसार संशोधन कर लें।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./476/19]

## TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

### NOTIFICATION

Mumbai, the 21st February, 2020

**No. TAMP/35/2016-Misc.**—In pursuance to the Ministry of Shipping, Government of India, letter No.PD-11033/73/2013-PT(Pt) dated 13 February 2020 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies the uniform procedure for levy of penal berth hire charges/incentive scheme under the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016, as in the Order appended hereto.

**Tariff Authority for Major Ports**

**Case No. TAMP/35/2016-Misc.**

### QUORUM

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

### ORDER

(Passed on this 20<sup>th</sup> day of February 2020)

The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PD-11033/73/2013-PT(pt) dated 16 June 2016 had forwarded the Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016. In this regard, we received proposals from 5 Major Ports viz. Kolkata Port Trust (KOPT), New Mangalore Port Trust (NMPT), Cochin Port Trust (COPT), Paradip Port Trust (PPT) and V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for prescription of incentive/penalty scheme for achievement/non-achievement of Performance Standards flowing from the Berthing Policy issued by the MOS. The proposals received from the above Ports have been disposed of by this Authority.

2.1. Now, the MOS has forwarded its letter No.PD-11033/73/2013-PT(Pt) dated 13 February 2020 regarding uniform procedure for levying penal berth hire charges. The contents of the said letter of the MOS are as follows:

- (i) The Berthing Policy for Dry Bulk Cargo for Major Ports, 2016 issued by the MOS laid down standardized guidelines for all Major Ports to compute performance norms for different dry bulk commodities. It also recommended penalties and incentive structures tied to the performance norms as part of the overall Berthing Policy. The objective of the performance linked incentive/disincentive structure is to continuously drive productivity improvements across ports and reward those exceeding the norms.
- (ii) The penal berth hire charges were levied by the VOCPT on ship agents for not achieving the performance norms fixed by the VOCPT for loading/unloading the commodities. However, the Tuticorin Ship Agents' Association (TSAA) objected to the levy of penal berth hire charges levied by VOCPT on the Ship Agents stating that any penalty or incentive is to be addressed to cargo handling agents like shippers/stevedores/receivers who are involved in cargo handling operations. The TSAA represented its case to the MOS and also submitted a representation to the IPA to relieve the agents from the responsibility of paying penal berth hire charges. The MOS requested IPA to look into the matter.
- (iii) The IPA initiated stakeholders consultation with all Major Ports, TAMP, Federation of Ship Agents Association (FEDSAA), Federation of Association of Stevedores (FAS)

and Federation of Freight Forwarders Association of India (FFFAI) with a proposal for prescribing responsibility on whom penal berth hire charge are to be imposed. The IPA also formed a small group to look into the matter.

- (iv) The Group, after going through the various inputs received from Ports and other stakeholders finalized its report and submitted to IPA. In the Report, the Group has recommended the following agencies on whom penal berth hire charges for various types of cargo are to be levied.

<b>Type of Cargo Handled</b>	<b>Penal Berth hire charges to be levied on</b>
Mechanized Bulk Berths	Shipping/Vessel Agents
Conventional Berths handling Dry Bulk/Break bulk cargo	Stevedoring Agents
Liquid Berths	Shipping/Vessel Agents

The Group also felt that uniform application of norms cannot be put in place in case of MOPT, NMPT and KOPT where port directly handles moderate volume of container cargo and localized arrangement are in existence. The Governing Body of IPA has approved the recommendation of the Group.

2.2. Based on the recommendation of the Group constituted by the IPA, the MOS has requested this Authority to notify the uniform procedure as recommended by the IPA for levy of penal berth hire charges for all Major Port Trusts excluding MOPT, NMPT and KOPT appropriately.

3.1. Thus, in pursuance of the MOS letter No.PD-11033/73/2013-PT(Pt) dated 13 February 2020, this Authority prescribes the following uniform procedure to be followed by all the Major Port Trusts except MOPT, NMPT and KOPT for levying penal berth hire charges/incentive scheme under the Berthing Policy, 2016 :

*“The following uniform procedure shall be followed by the Major Port Trusts for levy of penal berth hire charges and grant of incentive under the Berthing Policy, 2016 as per the relevant tariff approved by the Authority.*

<b>Type of Cargo Handled</b>	<b>Incentive to be granted and Penal Berth hire charges to be levied on the following agencies</b>
<i>Mechanized Bulk Berths</i>	<i>Shipping/Vessel Agents</i>
<i>Conventional Berths handling Dry Bulk/Break bulk cargo</i>	<i>Stevedoring Agents</i>
<i>Liquid Berths</i>	<i>Shipping/Vessel Agents</i>

3.2. Thus, the Major Port Trusts except MOPT, NMPT and KOPT are directed to amend the relevant tariff Order/Scale of Rates approved by this Authority, accordingly.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./476/19]